नईदुनिया

सैन्य कर्मियों के भारत लौटने से पहले तकनीकी टीम पहुंची मालदीव, विमानन प्लेटफॉर्म का संचालन संभालेगी

माले ।

सैन्य कर्मियों के पहले बैच के 10 मार्च तक मालदीव छोड़ने से पहले भारतीय तकनीकी कर्मियों की पहली टीम द्वीप राष्ट्र पहुंच गई है। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।

मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने बताया, भारतीय नागरिकों की पहली टीम पहुंच गई है। अब वे अड्डू में हेलीकॉप्टर का संचालन संभालेंगे। अड्डू में तैनात भारतीय सैन्य कर्मी दोनों देशों की सरकारों की सहमति से 10 मार्च तक वापस भारत लौट आएंगे। बयान में बताया गया कि बुधवार तक भारत से एक रिप्लेसमेंट हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा, जिसके बाद नागरिक टीम इसके संचालन को संभालने के लिए प्रशिक्षण अभ्यास शुरू कर देगी।

बता दें कि दो फरवरी को दोनों देशों ने सहमति जताई थी कि भारत अपने सैन्यकर्मियों को मार्च और मई के बीच मालदीव से वापस बुला लेगा। वहीं आठ फरवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बताया कि वर्तमान कर्मियों को भारतीय तकनीकी कर्मियों द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। वे मालदीव में दो हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान का संचालन जारी रखेंगे।

दोनों देशों के बीच हुई थी चर्चा

मालदीव ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि तीन विमानन प्लेटफार्मों में से एक में भारत सैन्य कर्मियों को 10 मार्च तक और अन्य को 10 मई तक बदल देगा। हालांकि, भारत ने सैनिकों को वापस लेने का कोई उल्लेख नहीं किया था। भारत की ओर से कहा गया, बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने साझेदारी को बढ़ाने के लिए कदमों की पहचान करने की दिशा में द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित व्यापक मुद्दों पर अपनी चर्चा जारी रखी। विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्ष भारतीय विमानन मंचों के निरंतर परिचालन के लिए परस्पर व्यावहारिक समाधान पर भी सहमत हुए जो मालदीव के लोगों को मानवीय और चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराते हैं।

बता दें कि मालदीव में करीबन 80 भारतीय सैन्यकर्मी इन प्लेटफॉर्म का संचालन करने के लिए तैनात हैं। पिछले साल राष्ट्रपति चुनावों के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का मुख्य मुद्दा भारतीय बलों को देश से बाहर निकालना था।

न्यूज ब्रीफ

मिशिगन में डेमोक्रेट की तरफ से बाइडन, रिपब्लिकन से ट्रंप की जीत, राष्ट्रपति चुनाव में फिर हो सकता है सामना

वॉशिंगटन । अमेरिका में इसी साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इस बीच डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए आंतरिक चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। जहां डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से अब तक सिर्फ जो बाइडन ही उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं, वहीं रिपब्लिकन पार्टी में निक्की हेली ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती पेश की है। हालांकि, ट्रंप अब तक सभी राज्यों में पार्टी के बाकी दावेदारों से आगे रहे हैं। मंगलवार को मिशिगन में बाइडन और ट्रंप दोनों ने प्राइमरी (पार्टी के आंतरिक मुकाबले) चुनाव में जीत हासिल की है। गौरतलब है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी इन प्राइमरी चुनावों में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी को ही राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार के तौर पर उतारती हैं। मिशिगन में राष्ट्रपति बाइडन ने अपनी लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी में अब तक अपने लिए चुनौती पेश कर रहे मिनेसोटा के प्रतिनिधि डीन फिलिप्स को शिकस्त दी। इसी के साथ पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत की। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के चार राज्यों में हुए आंतरिक चुनावों में अब तक एक में भी न हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में भी जीत हासिल कर ली। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली को एक बार फिर हराया। ट्रंप के अभियान के मुताबिक, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उतरने के लिए ट्रंप को मार्च के मध्य तक सभी राज्यों से कुल 1215 डेलिगेट्स (पार्टी के स्थानी नामित प्रतिनिधियों) के समर्थन की जरूरत होगी। अब तक ट्रंप ने कहां-कहां दर्ज की जीत रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रपति पद की दावेदारी पेश करने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप अब तक पांच राज्यों में जीत दर्ज कर चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले आईओवा में जीत के साथ शुरुआत की। इसके बाद नेवाडा, वर्जिन आईलैंड और दक्षिणी कैरोलाइना में भी ट्रंप ने निक्की हेली को हराकर राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी मजबूत की। अब मिशिगन में जीत के साथ वे पांच राज्यों के डेलिगेट्स का समर्थन हासिल कर चुके हैं। जो बाइडन अब तक किन राज्यों में रहे विजेता दूसरी तरफ राष्ट्रपति जो बाइडन दूसरे कार्यकाल के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के आंतरिक चुनाव में अब तक चार राज्यों में जीत हासिल कर चुके हैं। इनमें न्यू हैंपशर, दक्षिणी कैरोलाइना, नेवाडा शामिल हैं। मिशिगन में उनकी जीत के साथ ही राष्ट्रपति चुनाव में 2020 की तर्ज पर एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप बनाम जो बाइडन के बीच मुकाबले की अटकलें तेज हो गई हैं।

पाकिस्तान की सियासत : सीएममरियम की राह आसान नहीं; इमरान की पीटीआई ने विधानसभा का समानांतर सत्र बुलाने का एलान किया

लाहौर । पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने मुख्यमंत्री, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करने के लिए समानांतर पंजाब विधानसभा सत्र बुलाने की योजना बनाई है। उसने यह दावा किया कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मरयम नवाज चोरी किए गए जनादेश पर सदन में पहुंची हैं। पीटीआई ने दावा किया कि उसके समानांतर सत्र में 250 सदस्य शामिल हो सकते हैं। बता दें कि पीएमएल-एन की रयम नवाज ने इतिहास रचते हुए पंजाब की पहली महिला सीएम बनने का गौरव हासिलकिया है। उन्हें सीएम बनने के लिए 187 सीटों की जरूरत थी, जबकि मरयम को 220 मत मिले। उन्होंने पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राणा आफताब को हराया जबकि काउंसिल ने कार्यवाही का बहिष्कार किया था, जिसके चलते राणा को कोई वोट नहीं मिला था। आरक्षित सीट को अधिसूचित करना जरूरी जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी ने कहा, आरक्षित सीट अधिसूचित किए बिना प्रांतीय एसेम्बली का सत्र नहीं बुलाया जा सकता। एक दिन पहले पंजाब और सिंध की एसेम्बली का सत्र बुलाया गया और मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पार्टी नेता बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, पंजाबव सिंध एसेम्बली का सत्र गैर कानूनी ढंग से चलाया गया। यदि नेशनल एसेम्बली सत्र बुलाया जाता है तो वह भी अवैध होगा क्योंकि एसेम्बली को सदन के सभी सदस्यों को अधिसूचित करने के बाद ही बुलाया जाना चाहिए। इमरान और बुशरा बीबी आरोपी पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर भ्रष्टाचार मामले में आरोपी बनाया गया है। न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में सुनवाई की और आरोपपत्र पढ़ा। अल कादिर विवि ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों कैनाल भूमि के कथित अधिग्रहण के संबंध में खान, उनकी पत्नी व अन्य के खिलाफ जांच से सरकारी खजाने को 19 करोड़ पाउंड का नुकसान हुआ था। इस पर खान व बुशरा बीबी ने आरोपों से इनकार किया।

अफगानिस्तान में इस संगठन की बदौलत पनपा आईएसआईएल -के रिपोर्ट में खुलासा- ऐसे मिली हथियार जुटाने में मदद

संयुक्त राष्ट्र ।

संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट-खोरासन (आईएसआईएल-के) ने 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में छोड़े गए प्रतिबंधित तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के भंडार से हथियार मांगे और प्राप्त किए हैं।

अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर यूएन महासचिव की 18वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और अफ्रीका में हथियारों के प्रसार, विशेष रूप से हथियारों की पहुंच को लेकर चिंतित हैं। आईएसआईएल (दाएश) के क्षेत्रीय सहयोगियों ने छोटे हथियारों और हल्के हथियारों के साथ-साथ मानव रहित विमान प्रणालियों और तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों को उस तक पहुंचाने में वृद्धि की है।

सैन्य उपकरणों के प्रसार पर चिंता - संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफगानिस्तान के भीतर और पड़ोसी देशों में सैन्य उपकरणों के प्रसार पर चिंता व्यक्त की है। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया, कई सदस्य देशों ने बताया कि तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में बचे हथियारों के भंडार से हथियारों का प्रसार जारी है। सदस्य देशों ने रिपोर्ट करना जारी रखा कि आईएसआईएल-के ने तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान से ऐसे हथियार मांगे और प्राप्त किए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की वजह से क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को कमजोर कर दिया है।

सदस्य देशों ने बताया कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन-कैलिबर

हथियार जो आमतौर पर पूर्व अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों से जुड़े होते हैं, उन हथियारों को तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, टीआईपी जैसे तालिबान और अल-कायदा से जुड़े समूहों द्वारा आईएसआईएल-के में स्थानांतरित किया जा रहा है।

लड़ाकों की संख्या दो हजार से चार हजार होने का अनुमान - इस महीने जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सदस्य देशों ने आईएसआईएल-के को अफगानिस्तान और व्यापक क्षेत्र में सबसे गंभीर आतंकवादी खतरा माना है। रिपोर्ट के मुताबिक, आईएसआईएल-के ने अफगानिस्तान के अंदर अपनी परिचालन क्षमताओं में वृद्धि की है, जिसमें लड़ाकों और परिवार के सदस्यों की संख्या 2,000 से 4,000 होने का अनुमान है।

चुनाव आयोग जल्द जारी करेगा राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम, आसिफ अली जरदारी दौड़ में सबसे आगे

इस्लामाबाद । चुनाव आयोग (ईसीपी) एक मार्च को राष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम जारी कर सकता है, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के आसिफ अली जरदारी की जीत लगभग तय है। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। खबर के मुताबिक, 29 फरवरी को एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति चुनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद ईसीपी एक मार्च को राष्ट्रपति के चुनाव का आधिकारिक कार्यक्रम और सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा। समा टीवी ने ईसीपी के प्रवक्ता के हवाले से कहा, सभी चार प्रांतीय विधानसभाएं 29 फरवरी तक अस्तित्व में आएंगी और फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए जरूरी निर्वाचक मंडल के गठन का काम पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता शहबाज शरीफ के नेतृत्व में केंद्र में नई गठबंधन सरकार बनाने के लिए छह पक्षीय गठबंधन तैयार है। पीएमएल-एन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपी) के आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। जरदारी इससे पहले सितंबर 2008 से 2013 तक देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आठ फरवरी को हुए चुनाव के त्रिशंकु परिणाम सामने आए थे। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। जिसके बाद पीएमएल-एन और पीपीपी ने गठबंधन बनाने का फैसला किया। यह गठबंधन इस शर्त पर बना कि पीपीपी के आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति का पद मिलेगा। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री पद मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 41 के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव संपन्न होने के तीस दिनों के भी होना चाहिए। आठ फरवरी को आम चुनाव हुए थे। इसका मतलब 9 फरवरी से पहले राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। एक खबर में पहले कहा गया था कि ईसीपी राष्ट्रपति चुनाव नौ या दस मार्च को आयोजित करने के लिए तैयार है।

रूसी सेना में भर्ती नेपाली युवाओं की होगी स्वदेश वापसी, विदेश मंत्री बोले- हर संभव प्रयास करेगी सरकार

काठमांडू ।

रूस में अवैध तरीके से भर्ती किए गए नेपाली युवाओं को लेकर नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह सभी को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेंगे।

बताया जा रहा है कि 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच शुरू होने के बाद से ही सैकड़ों नेपाली नागरिक रूसी सेना में शामिल हो गए हैं। इस युद्ध में मॉस्को की ओर से लड़ते हुए अब तक 12 नेपाली नागरिकों की जान जा चुकी है।

नागरिकों की वापसी में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार

रूसी सेना में शामिल हुए नेपाली नागरिकों के परिवारों से बातचीत करते हुए सऊद ने कहा कि नेपाली युवाओं को अवैध माध्यमों से रूस नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागेगी और उन्हें अपने वतन वापस लाएगी। उन्होंने कहा, सरकार रूस से अपने नागरिकों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

नेपाली सरकार उपचार और बचाव का लाभ उठाने के लिए रूस में अपने दूतावास के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुसार सभी प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री के सचिवालय ने उनके हवाले से कहा कि युद्ध में घायल हुए लोगों और मृतकों के शवों को वापस लाया जाए।

संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं...

सऊद ने कहा, अब तक सरकार को 244 नेपाली नागरिकों के परिवारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो रूसी सेना में शामिल हुए हैं, जिनमें लापता लोग भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने लोगों से भ्रम से बचने के लिए रूसी सेना में भर्ती होने वाले नेपाली नागरिकों की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर न बताने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार रूसी पक्ष के संपर्क में है और रूस से नेपाली नागरिकों की वापसी पर चर्चा कर रही है।

डब्ल्यूटीओ के 70 से अधिक देश सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त दायित्व संभालेंगे, भारत को बड़ा लाभ

अबू धाबी ।

ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे 70 से अधिक देशों ने विश्व व्यापार संगठन के तहत अतिरिक्त दायित्व संभालने की पहल की है। इन देशों ने सेवा क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ के तहत समझौता किया है। इस वैश्विक संगठन के एक अधिकारी ने कहा कि 70 से अधिक देशों की इस पहल से भारत को बड़ा लाभ मिलने वाला है। खबर के मुताबिक देशों ने आपस में गैर-वस्तुओं के व्यापार को आसान बनाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। इस समझौते के तहत डब्ल्यूटीओ के अन्य सभी सदस्यों को समान रियायतें दी जाएंगी। रियायत के लिए सेवाओं में सामान पर सामान्य समझौते (जीएटीएस) किए जाएंगे। 70 से अधिक देशों ने यह अतिरिक्त दायित्व लेने पर स्वेच्छा से सहमति दी है। डब्ल्यूटीओ अधिकारी के मुताबिक जीएटीएस में देशों के शेड्यूल के तहत जो अतिरिक्त दायित्व उठाने का फैसला लिया गया है, इसमें लाइसेंसिंग जरूरतों और प्रक्रियाओं को कम करना सबसे अहम है। सहमति जताने वाले सभी देश योग्यता, जरूरत और प्रक्रियाओं और तकनीकी मानकों से संबंधित अनपेक्षित व्यापार प्रतिबंध के साथ-साथ प्रभाव या उपाय भी कम करना चाहते हैं।

राष्ट्रपति दावेदारी के लिए डेमोक्रेट नेताओं की पसंद बनीं मिशेल ओबामा, बाइडन को मिल सकती है चुनौती

वॉशिंगटन ।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन की जगह लेने के लिए प्रमुख पसंद बन चुकी है। रासमुसेन रिपोर्ट पोल्स में मतदान करने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के करीबन आधे नेताओं ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बाइडन के अलावा किसी अन्य पर अपनी पसंद व्यक्त की है।

राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक नेताओ की प्रमुख पसंद बनी मिशेल ओबामा

करीबन 48 फीसदी ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडन के अलावा अन्य उम्मीदवार को चुनने के लिए सहमति जताई है, जबकि 38 फीसदी ने इसपर असहमति जताई है। केवल 33 फीसदी ने मतदान में फेरबदल का अनुमान लगाया है। 81 वर्षीय जो बाइडन की जगह लेने के लिए मिशेल ओवामा को 20 फीसदी वोट मिले।

इस दौड़ में अन्य दावेदार उप राष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और मिशिगन के गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर शामिल हैं। कमला हैरिस को जहां 15 फीसदी तो वहीं हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप को 15 फीसदी वोट मिले।

मिशेल ओबामा ने व्यक्त की चिंताएं

बता दें कि मिशेल ओबामा को बार बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर विचार करने के लिए बुलाया जा रहा है। इससे पहले ओबामा ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि सरकार वास्तव में कुछ करती है और मै कहती हूं कि क्या सरकार हमारे लिए सबकुछ करती है। हम इस लोकतंत्र को हल्के में नहीं ले सकते हैं। मुझे कभी कभी चिंता

होती है कि हम ऐसा करते हैं।

2024 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोबारा मुकाबला होने की उम्मीद है। बाइडन ने इस दौरान खुद को सबसे योग्य उम्मीदवार होने का दावा किया है। वहीं ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव से पहले संभावित आपराधिक दोषसिद्धि के बावजूद चुनाव लड़ेंगे।

यूके सांसद बोलीं- भारतीय एजेंट्स सिखों को निशाना बना रहे

दावा- एजेंट्स की हिट लिस्ट में कई ब्रिटिश-सिख, हत्या की साजिशों का जिक्र किया

लंदन।

ब्रिटेन की सिख सांसद प्रीत कौर गिल का कहना है कि भारतीय एजेंट्स ब्रिटेन में रहने वाले सिखों को निशाना बना रहे हैं।

प्रीत कौर गिल ने ब्रिटिश संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) में सिखों के दमन का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन में रहने वाले सिख भारत से जुड़े एजेंट्स की हिट लिस्ट में हैं।

ब्रिटिश सिखों की सुरक्षा पर सवाल

गिल ने विदेशों में सिखों के खिलाफ कथित हत्या की साजिशों का जिक्र किया। साथ ही पूछा कि ब्रिटिश सिखों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की सरकार क्या कर रही है।

उन्होंने कहा- हाल के महीनों में फाइव आईज देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और यूके का इंटेलिजेंस अलायंस) ने यूनाइटेड किंगडम में सिख कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने वाले भारत से जुड़े एजेंटों की कार्रवाई पर चिंता जताई है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि कथित हत्याएं और हत्या की साजिशें नाकाम की गई हैं। अमेरिका और कनाडा ने ऐसे मामलों को अपनी संप्रभुता और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुनौती माना और इसे सार्वजनिक किया है। ब्रिटिश सिखों को भी इसी तरह के खतरों का सामना करने की रिपोर्ट्स को देखते हुए सरकार उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है

सुरक्षा मंत्री बोले- ब्रिटेन ऐसे मामले में फौरन कार्रवाई करेगा

सांसद प्रीत कौर गिल के सवाल के जवाब में सुरक्षा मंत्री टॉम तुगेनधाट ने कहा- यदि किसी

विदेशी से किसी भी ब्रिटिश नागरिक को कोई खतरा है, तो हम फौरन कार्रवाई करेंगे। सिख समुदाय को ब्रिटेन में हर दूसरे समुदाय की तरह सुरक्षित रहने का अधिकार है। सभी ब्रिटिश नागरिक समान हैं, चाहे उनका रंग, धर्म, आस्था या राजनीतिक निष्ठा कुछ भी हो। पिछले साल अमेरिका और कनाडा ने भारत पर आरोप लगाए थे।

1. कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगाया

18 जून 2023 की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गुरुद्वारा की पार्किंग में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर दो युवकों ने फायरिंग कर दी थी। निज्जर की मौके पर ही मौत हो गई। निज्जर को भारत ने भगोड़ा घोषित कर रखा था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। 3 महीने बाद यानी 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद में एक बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। ट्रूडो का इशारा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ था।

2. अमेरिका ने आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप लगाए

अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया था कि उसने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी जिसे अमेरिका ने नाकाम किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। कथित तौर पर यह साजिश भारत की ओर से रची जा रही थी और इसके जरिए पन्नू को निशाना बनाया जाना था।